1991-92 के दौरान लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की संख्या 600 थी ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, केंद्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है । वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात सरकार को 1,48,000/- रु० की केंद्रीय सहायता निर्मुक्त की गई ।

**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम**

1778. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य और आज की स्थिति के अनुसार उनकी लक्ष्य-वार उपलब्धियां क्या-क्या रही हैं ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) से (ग) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंश पूंजी से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है । यह निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम की तरह ही कार्य करेगा ।

**Members of minority community in Selection Boards**

1779. SHRI MOHAMMAD AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have issued any instructions for inclusion of members of minority communities in the Selection Boards constituted by the Government of India Undertakings;

(b) whether members belonging to minority communities have been included in all the Selection Commissions/Committees appointed for selection to different posts; and

(c) whether the Central Government have issued any instructions to the State Governments to include members of each community in their Selection Boards/Committees/Boards?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) Government have issued instructions in August 1990 that wherever a selection Committee/ Board exists or has to be constituted for making recruitment to 10 or more vacancies in Group C or Group D posts/services, it shall be mandatory to have one member belonging to SC/ST and one member belonging to minority community in such Committees/Boards. Wherever, however, the number of vacancies against which selection is to be made is less than 10, no effort should be spared in finding a SC/ST officer and a Minority Community Officer for inclusion in such Committees/Boards.

(c) One of the point in the Prime Minister's 15-Point Programme for the Welfare of Minorities envisages that the composition of Selection Committees should be representative.

**Wooing back Muslims**

1780. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which ap-